आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए।
– अज्ञात

प्रश्न अपनी जगह कायम

आखिर क्यों वे डर–डर कर जिंदा रहने को मजबूर हैं? सचाई यह है कि हमारी व्यवस्था महिला सुरक्षा के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। निर्भया कांड के बाद कई कानूनों में अहम बदलाव किए गए।

राम शुक्ला

तेलंगाना के हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के बाद उसे जिंदा जला दिए जाने की घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। सड़क से लेकर संसद तक इस पर आक्रोश भड़क उठा है। इस हादसे ने एक बार फिर सात साल पुराने निर्भया कांड की याद दिला दी है। आज हर देशवासी के भीतर यह सवाल है कि आखिर हमारा सिस्टम ठीक उसी तरह के हादसे भी क्यों नहीं रोक पा रहा है? जिस दिन हैदराबाद की घटना घटी उसके ठीक एक दिन पहले झारखंड की राजधानी रांची में बारह लोगों ने व्यस्त सड़क से एक लड़की को उठाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इन दोनों घटनाओं पर जब बवाल मचा तो दोषी पकड़ लिए गए और तेलंगाना वाले मामले में तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया।

शीघ्र सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित कर दिया गया है। लेकिन यह प्रश्न अपनी जगह कायम है कि हमारे शहर महिलाओं के लिए अब भी इतने असुरक्षित क्यों हैं? आखिर क्यों वे डर–डर कर जिंदा रहने को मजबूर हैं? पिछले साल आए थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे ने पूरी दुनिया में भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश बताया था। सचाई यह है कि हमारी व्यवस्था महिला सुरक्षा के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। निर्भया कांड के बाद कई कानूनों में अहम बदलाव किए गए।

पट्रोलिंग से लेकर एफआईआर के तौर–तरीकों और ट्रैफिक व्यवस्था तक में फेरबदल किए गए। पुलिस की सोच बदलने को लेकर भी काफी योजनों बनाई गईं।

2013 के केंद्रीय बजट में निर्भया फंड नाम से100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसकी राशि बढ़कर अभी 300 करोड़ हो चुकी है। इन बदलावों का मकसद ऐसे इंतजाम करना था कि महिलाएं घर से बाहर सुरक्षित रह सकें। देश में 600 ऐसे केंद्र खोले जाने थे, जहां एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला को चिकित्सा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श हासिल हो सके। सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, महिला थानों की संख्या बढ़ाने और नई हेल्पलाइनें शुरू करने की बात भी कही गई। मगर इन सब का नतीजा क्या निकला? यही कि तकरीबन रोज ही देश के किसी न किसी कोने से बलात्कार और हत्या की खबरें आ रही हैं। अपराधियों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं है। बलात्कार के मामले पहले से ज्यादा दर्ज होने लगे हैं लेकिन अपराधियों को सजा दिलाने की दर ज्यों की त्यों है।

अपराधी को सजा आज भी चार में एक मामले में ही मिल पाती है। इस स्थिति से उबरने का एक छोर यही है कि त्वरित न्याय हो और लोगों में सजा का खौफ दिखे। दूसरा छोर शहरों में पुलिस तंत्र की चौकसी से जुड़ा है। सड़कों पर गश्त इतनी होनी चाहिए कि अपराध करने से पहले अपराधी के हाथ कांप जाएं। इसके लिए जरूरी हो तो पूरे पुलिस बल की ओवरहॉलिंग की जाए। जितना भी पैसा लगे, लगाया जाए। हीला–हवाली का रवैया हमें कभी तो छोड़ना होगा।

बुद्धिमान गजानन

नवीन

धर्म-दर्शन

एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग–अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश ने शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतरू पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया।

संपादकीय

आबादी में असंतुलन

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आबादी रिपोर्ट–2019 में ऐसे कई ट्रेंड्स रेखांकित किए गए हैं जो हम सबसे सजग होने की मांग करते हैं। विश्व जनसंख्या में बढ़त–घटत के ये रुझान न केवल हमारी जीवन शैली से जुड़ी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं में बदलाव की जमीन तैयार कर रहे हैं बल्कि दुनिया की सभी सरकारों में इस मसले पर सहयोग और समन्वय की जरूरत भी बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक विश्व की जनसंख्या मौजूदा 770 करोड़ से बढ़ कर 970 करोड़ हो जाएगी। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर में लगभग हर जगह गिरावट दर्ज की जा रही है। वैश्विक स्तर पर प्रति महिला औसत जन्म दर 1990 में 3.2 थी जो 2019 में घटकर 2.5 रह गई। 2050 तक इसके और कम होकर 2.2 हो जाने का अनुमान है। किसी देश की आबादी घटने न लग जाए इसके लिए प्रति महिला औसत जन्म दर 2.1 होना जरूरी बताया जाता है।

बहरहाल, वैश्विक आबादी के इस बिगड़ते संतुलन को ध्यान में रखें तो आने वाले वर्षों में विभिन्न देश अकेले अपने स्तर पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। बेहतर होगा कि वैश्विक स्तर पर नीतियों, योजनाओं और कानूनों में समन्वय लाने के प्रयास अभी से किए जाएं ताकि जो बदलाव मांग और पूर्ति की कष्टप्रद प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, उन्हें ज्यादा सहज तरीके से संभव बनाया जा सके। जनसंख्या में जारी उथल–पुथल का ही दूसरा पहलू है आबादी के अलग–अलग आयु वर्गों का बदलता अनुपात। आबादी का ऐसा टेढ़ा अनुपात जल्द ही हमारे सामने बुजुर्गों की देखरेख और उनकी ऊर्जा के रचनात्मक उपयोग की चुनौती पेश करेगा, साथ ही हमें अपने कुछ स्थापित जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार के लिए भी बाध्य करेगा।

अरसे से महसूस किया जा रहा है कि हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ बुनियादी बीमारियां घर कर गई हैं। चुनावों का आलम यह है कि दो–चार महीने भी ऐसे नहीं गुजरते जब देश चुनावी मोड में न दिखता हो।

एक देश, एक चुनाव

रश्मि जोशी

केंद्र और राज्यों के चुनाव एकसाथ कराने को लेकर राजनीतिक नेतृत्व में आम सहमति तो क्या, व्यापक संवाद भी अभी नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश, एक चुनाव पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जिसमें जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा ने हिस्सा लिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, टीडीपी और टीएमसी की इस बैठक से गैरहाजिरी यह बताती है कि विपक्ष इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा।

बहरहाल, लगभग लगातार चुनाव हमारे सिस्टम का एक अहम मसला है जिसे फौरी राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। अरसे से महसूस किया जा रहा है कि हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ बुनियादी बीमारियां घर कर गई हैं। चुनावों का आलम यह है कि दो–चार महीने

भी ऐसे नहीं गुजरते जब देश चुनावी मोड में न दिखता हो। लोकसभा चुनाव जरूर इस सदी में पांच साल पर होते आ रहे हैं लेकिन राज्यों के चुनाव हर समय होते रहते हैं। इनके घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है जिससे सरकारें अहम फैसले नहीं ले पातीं और खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है।

एक अनुमान के मुताबिक, विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग–अलग होने से हर साल करीब चार महीने आचार संहिता के दायरे में आ जाते हैं। इसका उलट पक्ष यह कि कुछ राज्यों में अपना टेंपो हाई रखने के लिए केंद्र सरकार पॉपुलिस्ट फैसले लेने लगती है जिसका नुकसान बाकी राज्यों को होता है। राजनीति का मुहावरा ऐसा बदला है कि राज्यों में भी वोट केंद्र के फैसलों पर पड़ने लगे हैं। सूचना क्रांति ने पूरे देश को जोड़ दिया है। एक कोने में हो रहे चुनाव का असर पूरे देश पर पड़ता है। बढ़ता चुनावी खर्च एक अलग समस्या है जिससे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है। सैन्य बलों और बाकी अमले की तैनाती में पैसे तो लगते ही हैं, उनकी नियमित भूमिकाएं भी प्रभावित होती हैं। चुनाव एकसाथ कराए जाएं तो इन बीमारियों का असर कम हो सकता है।

सरकार बनने की कोई सूरत नहीं बनती तो क्या वहां मध्यावधि चुनाव नहीं कराए जाएंगे? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए लेकिन रास्ता तभी निकलेगा जब राजनीतिक दल चुनाव सुधार के बुनियादी प्रश्नों से कतराना छोड़ें। सिस्टम में बदलाव कभी आसान नहीं होता लेकिन उसमें गंभीर समस्याएं देखकर भी उनसे आंखें मूंदे रहना जिम्मेदारी से भागने जैसा है।

अष्टयोग-4890

	7				4	5
	33	1	23	6	33	
5		2	4			3
	28		27	4	36	
1	2			5		7
6	37	7	38		33	2
		5		3		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4889 का हल

1	5	4	3	2	7	6
2	30	7	31	4	34	2
6	3	2	4	5	7	1
5	37	6	33	6	29	3
7	5	3	6	1	2	4
3	30	5	32	7	34	5
4	2	1	6	3	5	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सुदूर मराठवाड़ा का सरकारी स्कूल बना मॉडल

शिरीष खरे। एक सरकारी शिक्षक ने पढ़ाने की एक नई पद्धति के सहारे बच्चों के लिए समय–सारणी से जुड़ी कुछ गतिविधियों को अमल में लाकर महज छह महीने में स्कूल की तस्वीर बदल दी है। इस दौरान यहां बच्चों की उपस्थिति एक तिहाई बढ़ गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के दूरदराज के गांव का यह स्कूल इन दिनों 'समय के सदुपयोग' के मुद्दे पर दूर–दूर तक चर्चा के केंद्र में है। यहां के शिक्षक ने सप्ताह में दो से तीन बार अतिरिक्त सत्र आयोजित किए और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया कि अधिकतर बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जाग गई। और तो और, उनमें अपने सहपाठियों के प्रति ऐसा लगाव भी पैदा हो गया कि आज पूरे स्कूल का वातावरण मैत्रीपूर्ण नजर आता है।

शिक्षक के कौशल और उनकी लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि बच्चों में आत्मविश्वास तो बढ़ ही रहा है, वे अपनी दिनचर्या के कई काम समय पर पूरे कर रहे हैं। बात हो रही है औरंगाबाद जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर के शासकीय प्राथमिक शाला बनशेंद्रा की।